



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-14/2016-17

बली दास एवं अन्य

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक

14.08.21

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता बली दास, पे0-स्व0 सुफल दास वो काली दास, पे0-स्व0 सुफल दास वो त्रिवेणी दास, पे0-स्व0 सुफल दास वो बलराम साह, पे0-स्व0 उधो साह वो मुनेश्वर दास, पे0-स्व0 सुफल दास वो अरविन्द दास, पे0-स्व0 घुटेश्वर दास सभी साकिनान-गंगटा फसिया, अंचल-गोड्डा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के रा0वि0 वाद सं0-31/2011-12 (शिवशंकर मंडल बनाम् घुटेश्वर दास वगै0) के आदेश दिनांक-18.06.13 के विरुद्ध दायर किया है। लेकिन बार-बार मौका देने के बावजूद अपीलकर्तागण के अनुपस्थित रहने के कारण उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उत्तरवादी सं0-2 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0-31/11-12 के आदेश दिनांक-18.06.13 के विरुद्ध अपीलकर्तागण की ओर से लम्बा अंतराल के बाद दिनांक-20.07.16 को अपील आवेदन दायर किया गया है। जबकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 66 के प्रावधान के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध 60 दिन के अंदर उपायुक्त के न्यायालय में अपील दायर किया जाना चाहिए था। लेकिन वर्तमान अपील आवेदन निम्न न्यायालय के आदेश के विरुद्ध तीन वर्ष के बाद दायर किया गया है। इस प्रकार समय सीमा के अंदर अपील वाद दायर नहीं किया गया है। इसलिए काल बाधित होने के कारण अपीलकर्तागण का अपील आवेदन खारिज होने योग्य है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्तागण के द्वारा दावा किया गया है कि अपीलवादगत जमीन उत्तरवादी सं0-2 के माता देवकी देवी से बंदोवस्ती पट्टा के द्वारा अपीलकर्तागण को प्राप्त हुआ है। लेकिन उनलॉगो का दावा गलत एवं

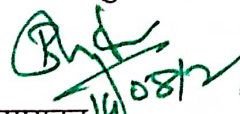
निराधार है। क्योंकि अपीलवादगत जमीन प्रधानी जोत जमीन है जिसका हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। उत्तरवादा सं०-2 शिवशंकर मंडल मौजा के प्रधान है। संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 69 के प्रावधान के अनुसार भी प्रधानी जोत जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है तथा संधाल परगना सेटलमेंट रेगूलेशन की धारा 18 भी प्रधानी जमीन पर किसी के दखल के आधार पर स्वामित्व कायम करने का अनुमति नहीं देता है। इसलिए अपीलकर्तागण का दावा नियम के विपरीत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

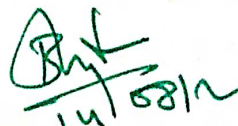
विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मतव्य है कि अपीलवादगत जमीन प्रधानी जोत है और उक्त जमीन प्रधान के उपयोग के लिए होता है। अपीलकर्तागण की ओर से नियम संगत कागजात भी दाखिल नहीं किया गया है एवं अपील आवेदन में जमीन का विवरण भी अंकित नहीं किया गया है। इसलिए अपीलकर्तागण का अपील आवेदन खारिज करने लायक है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, विज्ञ सहायक सरकारी वकील के मतव्य एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलवादगत जमीन प्रधानी जोत की जमीन है। संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 69 के तहत प्रधानी जोत भूमि का अंतरण पूर्णतः वर्जित है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा०वि० वाद सं०-31/2011-12 के दिनांक-18.06.2013 के आदेश बरकरार रखते हुए अपीलकर्तागण के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड्डा।


उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen
16/8/21

Seen
16/8/2021
डी०जी-139
01-09-2021